

सर्पदंश से युवक की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस

नई दिल्ली, 8 सितम्बर (एजेंसी): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने उत्तर प्रदेश में सर्पदंश के कारण एक युवक की मौत हो जाने के बाद सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने यह कदम उ.प्र. में चित्रकूट जिले के एक अस्पताल में मेडिकल लापरवाही और जीवन रक्षक आपातकालीन सुविधाओं की कमी के कारण सर्पदंश से एक युवक की मौत हो जाने की शिकायत के बाद उठाया है।

मामले की एक सितम्बर की कार्यवाही के अनुसार, शिकायतकर्ता का आरोप है कि सर्पदंश के तुरंत बाद पौड़ित को जिले के स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बावजूद, उसे समय पर आपातकालीन उपचार नहीं मिला — जिसमें 'एंटी-स्नेक वेनम' (सर्प विषरोधी दवा) और वेंटिलेटर या गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती करना शामिल है। इसकी अपेक्षा उसे बिना आवश्यक आपातकालीन ट्रांजिट सहायता के प्रयागराज रैफर कर दिया गया, जिससे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

NHRC ने बंद की जांच, HC पहुंचे पत्रकार राशिद

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : सोशल को नोटिस जारी किया।

मीडिया पर लगाए गए बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा बंद किए जाने के बाद पत्रकार उमर राशिद ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राशिद ने अज्ञात महिला वकीलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हाई कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत की उनकी मांग पर बुधवार को नोटिस जारी किया।

राशिद पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और 'जबरदस्ती बीफ खिलाने' के आरोप लगे थे

सुनवाई के दौरान याचिका पर नोटिस जारी किया। पत्रकार की ओर से वकील आदित एस. पुजारी पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। विवाद पिछले साल सोशल मीडिया पर की गई कुछ अज्ञात पोस्ट

से जुड़ा है, जिनमें राशिद पर गंभीर आरोप लगे थे।

Plaint against Harish: NHRC seeks report

The Hindu Bureau

HYDERABAD

The National Human Rights Commission has taken cognisance of a complaint regarding the failure to register an FIR over public allegations of 'black magic' and 'occult rituals' against Siddipet MLA and former Minister T. Harish Rao. The Commission directed the DGP, Telangana, to submit an Action Taken Re-

port within four weeks.

According to the complaint by Karupothula Revanth, no temple records, priest statements, receipts or other evidence supporting these allegations have so far been made public but there were repeated public allegations targeting Mr. Harish Rao that he had performed tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought.

NHRC seeks action taken report on Harish's complaint

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Hyderabad

THE National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday ordered Director General of Police (DGP) CV Anand to submit an action taken report on a complaint lodged on behalf of BRS leader T Harish Rao over non-registration of an FIR against Chief Minister A Revanth Reddy and others for leveling false allegations that the former minister performed "kshudra puja" (occult rituals).

The Commission directed the DGP to submit the report within four weeks.

The NHRC received a complaint on August 25 about non-registration of FIR in Hyderabad. The complaint was lodged by advocate Karupothula Revanth on behalf of Harish Rao, alleging that public office

holders in Telangana, including the chief minister and government whip, repeatedly imputed false accusations of "black magic," "occult practices," and "kshudra puja" against Harish Rao beginning on July 31, claiming he performed rituals to prevent rainfall and cause drought.

Despite written complaints lodged on August 4, and a detailed representation submitted on August 17 to DGP, no FIR was registered, no inquiry initiated and no reasons communicated, violating the Supreme Court's mandate in *Lalita Kumari v Government of UP*, the complaint said.

It sought relief, including registration of FIR, impartial investigation, preservation of electronic records and directions restraining public functionaries from attributing natural phenomena to sorcery.



अधूरे पुल से नदी पार करते स्कूली बच्चे, एनएचआरसी सख्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर : गरियाबंद जिले में स्कूली बच्चों के उफनती पैरी नदी पर अधूरे पुल से बंधी संकरी व फिसलन भरी लोहे की सीढ़ियां चढ़कर स्कूल जाने की घटना पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव विकास शील को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों पर बुधवार को संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने इसे गंभीर मामला बताया है। बता दें कि मैनपर ब्लाक

- गरियाबंद में 300 मीटर का पुल छह साल से अधूरा, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
- उफनती पैरी नदी में 20 फीट ऊंचे पिलर व संकरी सीढ़ियों से स्कूल जा रहे 30 से अधिक बच्चे



क्षेत्र में देहरगुड़ा और खंभाथा को जोड़ने वाला लगभग 300 मीटर लंबा यह पुल पिछले करीब छह वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। एनएचआरसी ने

कहा कि यह लंबा विलंब अधिकारियों द्वारा लगभग एक साल पहले स्थानीय ग्रामीणों को दिए गए उन स्पष्ट आश्वासनों के बाद हुआ है, जिसमें

निर्माण कार्य को छह महीने के भीतर पूरा करने का दावा किया गया था। मानसून के दौरान हो रही तेज वर्षा ने पैरी नदी का बहाव को अत्यंत खतरनाक और तेज बना दिया है, जिससे रोजाना इस कामचलाऊ सीढ़ी का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए जोखिम बहुत बढ़ गया है।

30 से अधिक बच्चे इसी तरह से नित्य स्कूल जाते हैं। नदी के दोनों ओर के गांवों का संपर्क कट जाता है। मानसून और भारी वर्षा के दौरान स्कूली बच्चे लगभग 20 फीट ऊंचे पिलर और लोहे की खतरनाक, संकरी सीढ़ियों (लेडर) के सहारे नदी पार करने को विवश होते हैं।

मानवाधिकार आयोग पहुंचा मुशहरी एनकाउंटर मामले में जांच की मांग

संवाद सहयोगी, जगरण • मुशहरी : थाना क्षेत्र के भाटोलिया नहर के पास प्रापटी डीलर अंकित रंजन हत्याकांड के आरोपित अमित कुमार के हाफ एनकाउंटर का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता देवव्रत कुमार सहनी ने आयोग में याचिका दायर की है। याचिका में घटना को संदिग्ध बताते हुए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। अब जांच सीबीआई एवं सीआईडी जैसी एजेंसी से कराने की मांग की गई है।

जानकारी हो की 17 जून की देर

रात पुलिस ने भटोलिया बांध पर विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान बदमाशों ने उन पर गोलीबारी की। जवाबी कारवाई में वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के रहने वाले बदमाश अमित सिंह के पैर में गोली लगी थी। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता की देवव्रत कुमार सहनी ने आरोप लगाया कि आरोपित को गिरफ्तार कार्यालय में पेश करने के बजाए पैर में गोली मारना संदिग्ध प्रतीत होता है।

अधूरे पुल से नदी पार करते बच्चों पर एनएचआरसी ने सीएस से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.रायपुर : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्कूली बच्चों के उफनती पैरी नदी पर अधूरे पुल से बंधी संकरी व फिसलन भरी लोहे की सीढ़ियां चढ़कर स्कूल जाने की घटना पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने इसे गंभीर मामला बताया है। बता दें कि मैनपुर ब्लाक क्षेत्र में देहरगुड़ा और खंभाथा को जोड़ने वाला लगभग 300 मीटर लंबा यह पुल पिछले करीब छह वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। एनएचआरसी ने कहा कि यह लंबा विलंब अधिकारियों द्वारा लगभग एक साल पहले स्थानीय

- छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 300 मीटर का पुल छह साल से अधूरा, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

ग्रामीणों को दिए गए उन स्पष्ट आश्वासनों के बाद हुआ है, जिसमें निर्माण कार्य को छह महीने के भीतर पूरा करने का दावा किया गया था। मानसून के दौरान हो रही तेज वर्षा ने पैरी नदी का बहाव को अत्यंत खतरनाक और तेज बना दिया है, जिससे रोजाना इस कामचलाऊ सीढ़ी का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए जोखिम बहुत बढ़ गया है। 30 से अधिक बच्चे इसी तरह से नित्य स्कूल जाते हैं। नदी के दोनों ओर के गांवों का संपर्क कट जाता है। मानसून और भारी वर्षा के दौरान स्कूली बच्चे लगभग 20 फीट ऊंचे पिलर और लोहे की खतरनाक, संकरी सीढ़ियों (लेडर) के सहारे नदी पार करने को विवश होते हैं।

Source: <https://news.abplive.com/technology/ncpcr-meets-meta-india-chief-takes-up-instagram-s-child-abuse-material-ad-1865968>

NCPCR Meets Meta India Chief, Takes Up Instagram's Child Abuse Material Ad

The matter concerns child sexual abuse material and advertisements related to such content on Meta's social media platform Instagram.

Written By : Varun Bhasin | Updated at : 09 Sep 2026 05:46 PM (IST)

Senior Meta officials on Wednesday met representatives of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) over a case involving child sexual abuse material (CSAM) on Instagram. The meeting lasted nearly an hour.

The Meta India MD and Head were not present at the meeting.

Case Involves Child Sexual Abuse Content On Instagram

The matter concerns child sexual abuse material and advertisements related to such content on Meta's social media platform Instagram.

The NCPCR had taken suo motu cognisance of a report and issued a notice to Meta Platforms Inc. on July 3, seeking a response in the matter.

Meta submitted its response around a week later. Following this, the NCPCR decided to initiate a formal investigation into the case.

Several Government Bodies Taking Action

The NCPCR is not the only government body looking into the matter. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Parliamentary Committee on Information Technology and the National Human Rights Commission (NHRC), among other government institutions, are also taking action in the case.

Meta Continues To Run Ads With Child Sexual Abuse

Meta ran hundreds of paid advertisements featuring artificial intelligence-generated child sexual abuse material (CSAM), including dozens in India, over the past 10 months, according to a new report by US-based campaigners.

The findings come two months after the Indian government ordered Meta to remove all ads and content promoting CSAM on Instagram. The order followed a BBC Eye investigation that found Instagram was running paid advertisements promoting CSAM in India.

ALSO READ: iPhone Foldable Design Fully Leaked By Accessory Maker Dbrand: Real Or Fake?

332 Ads Identified On Facebook, Instagram

The Washington-based Tech Transparency Project (TTP) said it identified 332 advertisements containing CSAM that ran on Facebook and Instagram. The majority — 274 ads — appeared in August this year.

The TTP report, published on Tuesday, said it identified several photographs of real children, including a member of a European royal family, which were used in the advertisements and subsequently manipulated using AI.

More than a dozen advertisements continued to appear on Meta's platforms even after TTP informed the company about its findings, the report said.

84 Ads Ran In India

Of the 332 advertisements identified by TTP, 84 ran in India. According to the report, 78 of those ads were published after the Indian government's order to remove CSAM and its meeting with senior Meta officials.

Following the BBC investigation, several Indian agencies, including the National Commission for Protection of Child Rights and the National Human Rights Commission, said they were examining the matter.

Meta Says It Does Not Tolerate Child Exploitation

Responding to the TTP findings, Meta said it does not tolerate "nudify apps or any kind of child exploitation, whether real or AI-generated".

"We don't tolerate nudify apps or any kind of child exploitation, whether real or AI-generated. These criminals constantly shift tactics to evade detection, which is why we keep strengthening our detection and enforcement," the company said in a statement.

Meta also told the BBC during its investigation that when it becomes aware of apparent child exploitation, it reports the material to the US-based National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), in compliance with its legal obligations.

NCMEC is the centralised global reporting system for the online sexual exploitation of children.

Source: <https://news.abplive.com/education/chhattisgarh-schoolchildren-forced-to-risk-river-crossing-via-unfinished-bridge-nhrc-seeks-report-1866041>

English News Education Chhattisgarh Schoolchildren Forced To Risk River Crossing Via Unfinished Bridge: NHRC Seeks Report

Chhattisgarh Schoolchildren Forced To Risk River Crossing Via Unfinished Bridge: NHRC Seeks Report

NHRC seeks a report from Chhattisgarh Chief Secretary after schoolchildren reportedly cross the swollen Pairi River via an unfinished bridge.

Written By : ABP Live Education | Updated at : 10 Sep 2026 10:06 AM (IST)

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday took suo motu cognisance of reports about dozens of schoolchildren from Khambhatha and nearby settlements in Chhattisgarh's Gariyaband district being forced to cross the swollen Pairi River to reach their schools.

The children reportedly use a narrow and slippery iron ladder attached to an incomplete bridge to make the crossing. The NHRC observed that the situation raises severe human rights concerns related to the safety and education of the children.

NHRC Issues Notice To Chhattisgarh Chief Secretary

Following the report, the NHRC issued an official notice to the Chief Secretary of the Government of Chhattisgarh. The commission has sought a detailed report on the matter within two weeks.

The action follows a media report dated September 3, 2026, which highlighted the difficulties faced by the schoolchildren while travelling to their schools.

Bridge Between Deharguda And Khambhatha Incomplete For Years

The roughly 300-metre-long bridge connects Deharguda and Khambhatha in the Mainpur Block area of Gariyaband district.

According to the media report, construction of the bridge has remained incomplete for nearly six years. The delay has continued despite assurances given by authorities to local villagers around a year ago that the work would be completed within six months.

ALSO READ: Want To Study At IIT Madras Without JEE? Apply For BS Programme 2026, Check Who Can Apply

Monsoon Increases Risk For Schoolchildren

The ongoing monsoon season has made the situation more dangerous. The shallow Pairi River has turned into a dangerous torrent, increasing the risk for students who are forced to use the makeshift ladder structure every

day.

The NHRC's notice has sought a detailed report from the Chhattisgarh Chief Secretary on the situation involving the schoolchildren and the unfinished bridge.

Published at : 10 Sep 2026 10:06 AM (IST)

Source: <https://www.edexlive.com/amp/story/news/nhrc-steps-in-after-reports-surface-of-chhattisgarh-pupils-using-narrow-ladder-to-cross-river>

News

NHRC steps in after reports surface of Chhattisgarh pupils using narrow ladder to cross river

Notice sent to state authorities demanding answers over schoolchildren in Gariyaband allegedly crossing a river on an iron ladder to reach classrooms

IANIS

Updated:9th Sep, 2026 at 9:50 PM

New Delhi, Sep 9 (IANIS): The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports that dozens of schoolchildren in Chhattisgarh's Gariyaband district are forced to cross a river using a narrow and slippery iron ladder attached to an unfinished bridge to reach their schools.

Observing that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights, the apex human rights body has issued a notice to the Chhattisgarh Chief Secretary, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, children from Khambhatha and nearby settlements in the Mainpur Block area are compelled to climb the iron ladder attached to an incomplete bridge to cross the Pairi river and attend school.

The report said the shallow river turns into a torrent during the monsoon, making the crossing particularly hazardous for the children.

According to the media report, carried on September 3, a roughly 300-metre-long bridge between Deharguda and Khambhatha in Mainpur Block has been under construction for nearly six years. The villagers were reportedly assured by the concerned authorities about a year ago that the bridge would be completed within six months. However, the construction remains incomplete, leaving schoolchildren and residents dependent on the hazardous crossing.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, embodies India's concern for the promotion and protection of human rights. Its primary role is to protect and promote human rights, defined as rights relating to life, liberty, equality and dignity of individuals, guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Source: <https://www.siasat.com/brs-knocks-on-governors-door-over-assembly-chaos-suspensions-3539169/>

BRS knocks on Governor's door over Assembly chaos, suspensions

The party said it will approach the National Commission for Women and the National Human Rights Commission if the Governor fails to act.

Veena Nair | Published: 9th September 2026 4:26 pm IST | Updated: 9th September 2026 4:49 pm IST

Hyderabad: Bharat Rashtra Samithi (BRS) leaders, led by KT Rama Rao (KTR) and Harish Rao, submitted a representation to Telangana Governor Shiv Pratap Shukla, calling the chaotic first two days of the Monsoon Session of the Legislative Assembly a constitutional breakdown.

The letter highlighted what unfolded on Monday and Tuesday, leading to the assault on its leaders, including women legislators P Sabitha Indra Reddy and V Sunita Laxma Reddy; the arrests and subsequent suspension of MLCs Tata Madhusudhan and N Naveen Reddy; the suspension of BRS MLAs and an open death threat allegedly issued by Shadnagar MLA Veerlapally Shankar against K Chandrashekar Rao (KCR), as well as the police inaction over the threat.

The letter mentions the Telangana High Court's hearing on the assault of BRS MLAs and directing the Director General of Police (DGP) to submit a detailed report on the matter.

Within hours of that order, the Saifabad Police registered two first information reports (FIRs), one naming 14 BRS MLAs, and another invoking the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act against MLCs Tata Madhu and Naveen Reddy. They were arrested on September 8. Even as the court declined to remand them, the state government moved resolutions the same day suspending them from the Legislative Council for the rest of the Monsoon Session," states the letter.

"The Congress government has justified the suspension of the 21 BRS MLAs separately, saying they stormed the Speaker's podium demanding a debate on Shankar's remarks and refused repeated requests from the Speaker and Congress ministers to return to their seats before a motion moved by Minister D Sridhar Babu was passed," the letter reads.

The representation asks Governor Shukla to advise the Speaker and Council Chairman to reconsider the suspensions, order an FIR against erring police personnel involved in the alleged assault, preserve CCTV footage for the High Court and arrange adequate security for KCR's residence.

Addressing reporters in front of the Governor's residence, KTR said that the party had apologised for the remarks made by Tata Madhusudhan against Speaker Gaddam Prasad Kumar. "Even after tendering an apology to the floor, our MLCs remain suspended," he said.

The BRS working president said that the party will approach the National Commission for Women and the National Human Rights Commission if the Governor fails to act. "Our MLAs and MLCs are being penalised for

protesting, which is a constitutional right, while more serious conduct by the ruling government goes unnoticed," he said.

Source: <https://thenewsmill.com/2026/09/meta-india-meets-ncpcr-over-child-exploitation-ad-allegations/>

Nation and Beyond

Meta India meets NCPCR over child exploitation ad allegations

By TNM (With ANI Inputs) 9 September 2026, 4:52 pm

Representatives of Meta India attended the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) office on September 9 following the summoning of the company's Managing Director and Head of Meta India as part of an inquiry into alleged advertisements related to Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM).

The NCPCR had initiated the process after taking suo motu cognisance of a BBC Eye media report that highlighted alleged advertisements on Meta-owned platforms. On July 3, 2026, the Commission issued a notice to Meta Platforms, Inc. requesting an explanation concerning these allegations.

Meta provided a response a week after receiving the notice. After reviewing the company's reply, the NCPCR resolved to conduct an inquiry to verify the facts and circumstances around the allegations.

In ongoing proceedings, the NCPCR summoned the Managing Director and Head of Meta India to appear before it on September 9 to furnish additional information regarding the allegations and Meta's response. The inquiry aims to establish the facts and scrutinise the company's handling of the matter.

Earlier, the National Human Rights Commission (NHRC) directed the Delhi Police to undertake a comprehensive investigation into claims that paid advertisements on Meta-owned Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India. The NHRC also ordered an examination to determine whether Meta and other relevant entities complied with mandatory reporting requirements under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The NHRC's action followed reports by the BBC World Service alleging that advertisements on Instagram contained specific expressions that directed users to channels where such material was purportedly available for sale.

In a letter dated July 8, the NHRC instructed the Delhi Police Commissioner to submit a detailed Action Taken Report (ATR). These proceedings commenced after a complaint or intimation dated July 6 was submitted to the Commission. Subsequently, on July 29, the NHRC sent another letter to the Delhi Police requesting the required report.

Source: <https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3974949-meta-india-faces-scrutiny-over-alleged-child-exploitation-ads>

Meta India Faces Scrutiny Over Alleged Child Exploitation Ads

Meta India's senior officials were summoned by the National Commission for Protection of Child Rights due to allegations of advertisements promoting child exploitation on Meta platforms. Investigations are underway following media reports and inquiries by the National Human Rights Commission.

Devdiscourse News Desk | Updated: 09-09-2026 16:56 IST | Created: 09-09-2026 16:56 IST

On Wednesday, representatives from Meta India attended a meeting at the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) after the body summoned Meta India's Managing Director and Head. The summons were issued in response to a probe into alleged advertisements related to Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM) on Meta platforms.

NCPCR had taken immediate action following a BBC Eye report and issued a notice to Meta Platforms, Inc. on July 3, 2026, requesting an explanation on these serious allegations. Meta responded a week later, which prompted the Commission to initiate further inquiry to delve deeper into the situation.

The inquiry, which is in progress, requires the MD and Head of Meta India to attend a hearing on September 9 to discuss the claims and Meta's response. Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC) directed Delhi Police to investigate claims that paid ads on Instagram, a Meta-owned platform, promoted Child Sexual Abuse Material in India.

(With inputs from agencies.)

Source: <https://www.wionews.com/videos/meta-india-faces-child-rights-probe-over-alleged-instagram-ads-linked-to-child-abuse-material-1788968122532>

Meta India Faces Child Rights Probe Over Alleged Instagram Ads Linked To Child Abuse Material

Edited By WION Video Desk

Published: Sep 09, 2026, 21:05 IST | Updated: Sep 09, 2026, 21:05 IST

Meta India representatives appeared before India's National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) after the child rights body summoned the company's managing director and head over serious allegations involving Instagram advertisements. The inquiry follows a BBC investigation that alleged paid Instagram advertisements were being used to promote child sexual exploitation and abuse material, with users reportedly directed to Telegram channels where such material was allegedly sold. The NCPCR took suo motu cognizance of the report and later opened a formal inquiry after reviewing Meta's response. Separately, the National Human Rights Commission (NHRC) has directed Delhi Police to investigate the allegations and examine whether Meta and other concerned entities complied with mandatory reporting obligations under the POCSO Act. Both proceedings are currently focused on establishing the facts and determining whether any legal or regulatory obligations were breached.

Source: <https://thesouthfirst.com/tehangana/nhrc-asks-tehangana-dgp-to-act-against-those-who-accused-harish-rao-of-performing-black-magic/>

NHRC asks Telangana DGP to act against those who accused Harish Rao of performing black magic

The NHRC also directed the Director General of Police to submit an Action Taken Report in English within four weeks.

South First Desk

Published Sep 10, 2026 | 8:47 AM — Updated Sep 10, 2026 | 8:47 AM

Synopsis: The complainant said persons holding high public offices, including the Chief Minister and a Government Whip, repeatedly accused Rao of performing tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought. Although police complaints were lodged, no action was taken, prompting the complainant to approach the NHRC with Rao's authorisation. The NHRC has asked the DGP for an action-taken report within four weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC) has urged the Telangana state police chief to initiate action against those who had accused Siddipet MLA and former minister T Harish Rao of indulging in black magic and occult rituals.

The NHRC made the recommendation based on a complaint regarding the failure to register a first information report over the public allegations against the BRS leader.

Telangana High Court Advocate and social activist Karupothula Revanth lodged the complaint, with the authorisation of Rao, under Section 12(a) of the Protection of Human Rights Act, 1993, on 22 August, the complainant said in a statement.

The NHRC also directed the Director General of Police (DGP), Telangana, to submit an Action Taken Report (ATR) in English within four weeks. The Commission issued the direction on Wednesday, 9 September.

Also Read: How Telangana serial killer lured 11 victims across 3 states

The complaint

Adv Revanth complained that persons holding high public offices, including the Chief Minister and a Government Whip, have been repeatedly alleging since 31 July that Rao had performed tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought.

The complainant said no evidence supporting the accusation was made public.

It further stated that complaints were submitted to Osmania University and the Vanasthalipuram police on 4 August. A representation was also made to the DGP's office on 17 August. However, no FIR was registered, and no reasons were communicated for the failure to register the case.

The complainant also referred to the Supreme Court judgment in Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh,

(2014) 2 SCC 1, regarding the registration of FIRs in cognisable offences.

The complaint expressed concern that public statements by people in high constitutional and political office linking rainfall or drought to occult practices could promote superstition among the public. It also warned that such claims could encourage accusations of witchcraft in rural areas and potentially lead to attacks against women, widows, elderly persons and members of SC/ST communities.

“If an ordinary citizen makes such allegations, a case would be registered immediately. But when people in positions of power make such statements, no action is taken. That is the reason this complaint was filed,” Adv Revanth said.

Telangana has reported a 23 per cent rainfall deficit between 1 June and 9 September 2026. According to the India Meteorological Department forecast, the state is likely to receive thunderstorms and isolated, below-normal rainfall until 16 September.

Source: <https://www.arthparkash.com/chitrakoot-snake-bite-death-nhrc-notice>

चित्रकूट में सांप के काटने से युवक की मौत पर NHRC सख्त, सभी राज्यों को भेजा नोटिस; 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
By Yogesh -- Wednesday, 09 Sep, 2026

चित्रकूट में सांप के काटने से युवक की मौत, NHRC सख्त; सभी राज्यों को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में सांप के काटने के बाद एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को समय पर जरूरी इलाज और एंटी-स्नेक वेनम (ASV) नहीं मिल सका। गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा है कि सांप के काटने वाले और दूरदराज के इलाकों में एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

खांडेहा गांव के युवक को सांप ने काटा
मामला चित्रकूट जिले के खांडेहा गांव का बताया जा रहा है। यहां एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया था। परिजन उसे बिना देर किए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

आरोप है कि जिला अस्पताल में युवक को समय पर एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उसकी हालत गंभीर होने के बावजूद अस्पताल में वेंटिलेटर या ICU जैसी जरूरी आपातकालीन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया।

प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में मौत
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवक को पर्याप्त आपातकालीन चिकित्सा सहायता के बिना प्रयागराज रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई।

इस मामले में इलाज में कथित लापरवाही और सरकारी अस्पताल में जरूरी जीवनरक्षक सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है।

NHRC ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए संज्ञान लिया है। NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से यह जानकारी मांगी है कि सांप के काटने की घटनाओं वाले हाई-रिस्क इलाकों में एंटी-स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

2 हफ्ते में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट
NHRC ने मामले में लगाए गए आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने यह भी कहा है कि दूरदराज और सांप के काटने की घटनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए। ऐसे इलाकों में सर्पदंश के मामलों का वास्तविक आंकड़ा जुटाने और मरीजों को बिना देरी के जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर उठे सवाल
चित्रकूट की इस घटना ने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्पदंश के मामलों में इलाज में देरी मरीज के लिए बेहद गंभीर साबित हो सकती है।

ऐसे में जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और जरूरत पड़ने पर मरीज को सुरक्षित तरीके से उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है।

NHRC का ताजा कदम इसी बात पर केंद्रित है कि सांप के काटने जैसे आपातकालीन मामलों में मरीज को उसके नजदीकी सरकारी अस्पताल में समय पर जरूरी इलाज मिल सके।

अब अधिकारियों से मांगा गया जवाब

चित्रकूट के इस मामले के बाद अब संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि जिला अस्पताल में सर्पदंश के इलाज की क्या व्यवस्था थी और युवक को समय पर जरूरी उपचार क्यों नहीं मिल सका।

NHRC की जांच और राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट के बाद यह भी सामने आ सकता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सर्पदंश के मरीजों के लिए एंटी-स्नेक वेनम और अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति क्या है।

फिलहाल, चित्रकूट मामले में NHRC के नोटिस के बाद सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश के इलाज की व्यवस्था और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

Source: <https://newsable.asianetnews.com/amp/india/meta-india-reps-appear-before-ncpcr-over-alleged-cseam-ad-inquiry-articleshow-of7beun>

Meta India reps appear before NCPCR over alleged CSEAM ad inquiry

Asianet News Central | ANI

Published : Sep 09, 2026, 05:00 PM IST

Synopsis

Meta India representatives appeared before the NCPCR after being summoned over an inquiry into alleged ads for Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM). The probe follows a BBC report, and the NHRC has also ordered a police investigation.

Representatives of Meta India arrived at the office of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on Wednesday after the child rights body summoned the company's Managing Director and Head of Meta India in connection with an inquiry into alleged advertisements related to Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM).

The NCPCR had taken suo motu cognisance of a media report published by BBC Eye regarding alleged advertisements on Meta-owned platforms and issued a notice to Meta Platforms, Inc. on July 3, 2026, seeking an explanation over the allegations. Meta submitted its response to the Commission a week after the notice was issued. After examining the response, the NCPCR decided to institute an inquiry to ascertain the facts and circumstances surrounding the matter. As part of the ongoing proceedings, the Commission summoned the MD and Head of Meta India to appear before it on September 9 and provide further information regarding the allegations and the company's response. The inquiry is aimed at determining the facts surrounding the allegations and examining the response submitted by Meta, the Commission said.

NHRC Directs Police Probe

The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier directed the Delhi Police to conduct a comprehensive probe into allegations that paid advertisements on Meta-owned Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India. The NHRC also directed the police to examine whether the technology company and other concerned entities complied with mandatory reporting obligations under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

Representatives of Meta India arrived at the office of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on Wednesday after the child rights body summoned the company's Managing Director and Head of Meta India in connection with an inquiry into alleged advertisements related to Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM).

The NCPCR had taken suo motu cognisance of a media report published by BBC Eye regarding alleged advertisements on Meta-owned platforms and issued a notice to Meta Platforms, Inc. on July 3, 2026, seeking an explanation over the allegations. Meta submitted its response to the Commission a week after the notice was issued. After examining the response, the NCPCR decided to institute an inquiry to ascertain the facts and

circumstances surrounding the matter. As part of the ongoing proceedings, the Commission summoned the MD and Head of Meta India to appear before it on September 9 and provide further information regarding the allegations and the company's response. The inquiry is aimed at determining the facts surrounding the allegations and examining the response submitted by Meta, the Commission said.

NHRC Directs Police Probe

The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier directed the Delhi Police to conduct a comprehensive probe into allegations that paid advertisements on Meta-owned Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India. The NHRC also directed the police to examine whether the technology company and other concerned entities complied with mandatory reporting obligations under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

Source: <https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-demands-report-from-chhattisgarh-chief-secy-over-schoolchildren-forced-to-cross-river-via-unfinished-bridge-7597361.html/amp>

India News | NHRC Demands Report from Chhattisgarh Chief Secy over Schoolchildren Forced to Cross River Via Unfinished Bridge

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The National Human Rights Commission (NHRC), on Wednesday, took suo motu cognisance of reports that dozens of schoolchildren from Khambhatha and neighbouring settlements in Chhattisgarh's Gariyaband district are forced to scale a narrow, slippery iron ladder attached to an incomplete bridge to cross the swollen Pairi River to reach their schools.

ANI Sep 09, 2026 09:54 PM IST

New Delhi [India], September 9 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC), on Wednesday, took suo motu cognisance of reports that dozens of schoolchildren from Khambhatha and neighbouring settlements in Chhattisgarh's Gariyaband district are forced to scale a narrow, slippery iron ladder attached to an incomplete bridge to cross the swollen Pairi River to reach their schools.

Observing that the report raises severe human rights concerns regarding the safety and education of children, the NHRC issued an official notice to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, demanding a detailed report within two weeks.

According to the media report dated September 3, 2026, the roughly 300-meter-long bridge connecting Deharguda and Khambhatha in the Mainpur Block area has remained incomplete for nearly six years.

The prolonged delay comes despite explicit assurances given by authorities to local villagers about a year ago that construction would be finished within six months.

The ongoing monsoon season has turned the shallow Pairi River into a dangerous torrent, severely heightening the risk for students forced to use the makeshift ladder structure daily. (ANI)

Source: <https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-seeks-report-after-chhattisgarh-children-forced-to-cross-river-on-unsafe-iron-ladder>

NHRC Seeks Report After Chhattisgarh Children Forced To Cross River On Unsafe Iron Ladder

The NHRC has sought a report from the Chhattisgarh government after reports showed children in Gariyaband district crossing the Pairi River using a narrow, slippery iron ladder attached to an unfinished bridge. The 300-metre bridge between Deharguda and Khambhatha has reportedly remained incomplete for nearly six years, forcing students to risk their safety during monsoon.

FPJ News Service Updated: Wednesday, September 09, 2026, 07:55 PM IST

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that dozens of children from Khambhatha and nearby settlements in the Mainpur Block area of Gariyaband district in Chhattisgarh are compelled to climb a narrow and slippery iron ladder, attached to an unfinished bridge, to cross the Pairi river to reach their schools. Reportedly, the monsoon turns the shallow river into a torrent.

NHRC seeks report from Chhattisgarh

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Therefore, it has issued a notice to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 3rd September 2026, a roughly 300-metre-long bridge between Deharguda and Khambhatha in Mainpur Block has been under construction for nearly six years despite the villagers having been assured of its completion in six months by the concerned authorities about a year ago.

Source: <https://udaipurkiran.com/nhrc-takes-action-over-unsafe-river-crossing-for-school-children-in-chhattisgarh/>

NHRC Takes Action Over Unsafe River Crossing for School Children in Chhattisgarh
9 Sep 2026 11:47 PM by Bhupendra Singh Chundawat

Gariaband, September 9 (Udaipur Kiran) : The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of alarming reports from Gariaband district in Chhattisgarh, where numerous school children are compelled to cross a river using a narrow and slippery iron ladder connected to an incomplete bridge. Local News

According to media reports, this situation poses a serious violation of human rights. In response, the NHRC has issued a notice to the Chief Secretary of Chhattisgarh, demanding a detailed report on the matter within two weeks.

Children from the Khambatha area and nearby settlements in the Mainpur block reportedly have to climb this iron ladder to cross the Pari River to reach school. The river, which is relatively shallow, becomes perilously swollen during the monsoon season, making it extremely dangerous for the children to navigate.

Reports indicate that the construction of a bridge spanning approximately 300 meters between Deharaguda and Khambatha in the Mainpur block has been ongoing for the past six years. Local authorities had assured villagers about a year ago that the bridge would be completed within six months; however, the work remains unfinished, forcing school children and local residents to risk their safety by using this hazardous route.

Established under the Human Rights Protection Act of 1993, the NHRC is an autonomous statutory body that reflects India's commitment to promoting and protecting human rights. Its primary role is to safeguard rights related to life, liberty, equality, and dignity, as guaranteed by the Constitution or included in international agreements enforceable in Indian courts.

The NHRC has the authority to take action based on media reports, public information, or other sources, even without formal complaints of human rights violations.

Source: <https://menafn.com/1111642623/NHRC-Notice-To-Chhattisgarh-Over-Students-Using-Ladder-On-Unsafe-Bridge>

NHRC Notice To Chhattisgarh Over Students Using Ladder On Unsafe Bridge

Date 2026-09-09 12:16:22

MENAFN- AsiaNet News)

NHRC Issues Notice to Chhattisgarh Govt

The National Human Rights Commission (NHRC), on Wednesday, took suo motu cognisance of reports that dozens of schoolchildren from Khambhatha and neighbouring settlements in Chhattisgarh's Gariyaband district are forced to scale a narrow, slippery iron ladder attached to an incomplete bridge to cross the swollen Pairi River to reach their schools. Observing that the report raises severe human rights concerns regarding the safety and education of children, the NHRC issued an official notice to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, demanding a detailed report within two weeks.

Bridge Incomplete for Six Years

According to the media report dated September 3, 2026, the roughly 300-meter-long bridge connecting Deharguda and Khambhatha in the Mainpur Block area has remained incomplete for nearly six years. The prolonged delay comes despite explicit assurances given by authorities to local villagers about a year ago that construction would be finished within six months. The ongoing monsoon season has turned the shallow Pairi River into a dangerous torrent, severely heightening the risk for students forced to use the makeshift ladder structure daily. (ANI)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a syndicated feed.)

Source: <https://www.thehansindia.com/news/cities/hyderabad/nhrc-directs-telangana-dgp-to-take-action-against-those-who-made-unsubstantiated-black-magic-allegations-against-harish-rao-1120036>

NHRC Directs Telangana DGP to Take Action Against Those Who Made Unsubstantiated Black Magic Allegations Against Harish Rao

In Short The complaint was filed before the NHRC by Telangana High Court advocate and social activist Karupothula Revanth, with the authorisation of Harish Rao.

The Hans India Created On: 9 Sept 2026 11:39 PM IST

Hyderabad: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint regarding the failure to register an FIR over public allegations of “black magic” and “occult rituals” against Siddipet MLA and former Minister T. Harish Rao. The complaint was filed before the NHRC by Telangana High Court advocate and social activist Karupothula Revanth, with the authorisation of Harish Rao. The Commission has directed the Director General of Police (DGP), Telangana, to submit an Action Taken Report (ATR) in English within four weeks. The direction was issued by the Commission on September 9, 2026. Advocate Karupothula Revanth filed the complaint on August 22, 2026, under Section 12(a) of the Protection of Human Rights Act, 1993. According to the complaint, since July 31, 2026, persons holding high public offices, including the Chief Minister and a Government Whip, have repeatedly made public allegations that Harish Rao had performed tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought.

The complaint states that no temple records, priest statements, receipts or other evidence supporting these allegations have so far been made public. It further states that complaints were submitted at the Osmania University and Vanasthalipuram Police Stations on August 4, 2026, followed by a representation at the DGP's office on August 17, 2026. However, according to the complaint, no FIR was registered and no reasons were communicated for the failure to register the case. The complainant also referred to the Supreme Court judgment in *Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh*, (2014) 2 SCC 1, regarding the registration of FIRs in cognisable offences. The complaint expressed concern that public statements by persons holding high constitutional and political offices linking rainfall or drought to occult practices could promote superstition among the public. It also warned that such claims could encourage accusations of witchcraft in rural areas and potentially lead to attacks against women, widows, elderly persons and members of SC/ST communities. Speaking on the matter, Advocate Karupothula Revanth said: “If an ordinary citizen makes such allegations, a case would be registered immediately. But when people in positions of power make such statements, no action is taken. That is the reason this complaint was filed.” The NHRC's direction to the Telangana DGP now requires the police authorities to report the action taken on the complaint within four weeks.

Source: <https://urbanacres.in/nhrc-directs-telangana-dgp-to-act-on-occult-rituals-claims/>

NHRC Directs Telangana DGP to Act on Occult Rituals Claims

By Urban Acres September 10, 2026

NHRC occult rituals case: The National Human Rights Commission has directed the Telangana director general of police to take action over alleged black magic and occult-ritual claims made publicly against Bharat Rashtra Samithi leader and former minister T Harish Rao, according to a report by The Times of India. The commission has sought an action-taken report from the DGP within four weeks.

The directive followed a complaint filed by Telangana High Court advocate Karupothula Revanth, who alleged that complaints over the statements were not registered as first information reports. The complaint was submitted to the NHRC after allegations attributed to people holding high public offices, including the chief minister and a government whip, linked Harish Rao to tantric or occult practices at temples and claimed that the acts were intended to stop rainfall and cause drought.

The allegations concern statements reportedly made from July 31, 2026. According to the complaint, no temple records, statements from priests, receipts or other supporting material had been made public to substantiate the claims. The complaint characterised the allegations as unsubstantiated and questioned the failure of the police to register a case or communicate the reasons for not doing so.

Revanth said complaints were submitted at the Osmania University and Vanasthalipuram police stations on August 4, followed by a representation to the DGP's office on August 17. The complaint alleged that no FIR had been registered in response to those submissions.

The NHRC's direction places the matter before the state police for action and reporting. The commission has not, in the material reported, determined whether the allegations against Harish Rao were true. Its intervention relates to the handling of the complaints and the alleged public statements, including whether they warrant police action under applicable law.

The complaint also raised a wider public-safety concern. It said that claims by people in senior constitutional and political positions linking rainfall or drought to occult practices could reinforce superstition. It warned that such narratives may contribute to accusations of witchcraft in rural areas and expose women, widows, elderly people and members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities to attacks.

The complainant argued that the response would have been different if similar allegations had been made by an ordinary citizen. The NHRC has now asked the Telangana DGP to submit the action-taken report within four weeks, which is the next formal milestone identified in the commission's direction.

Source: <https://theobserverpost.com/journalist-omar-rashid-files-defamation-suit-over-social-media-rape-beef-allegations/>

Journalist Omar Rashid Files Defamation Suit Over Social Media Rape, Beef Allegations

By The Observer Post

Published On: September 9, 2026 10:55 AM

Journalist Omar Rashid has filed a defamation suit before the Delhi High Court against a woman lawyer over social media posts that accused him of rape and forcing a woman to eat beef.

The suit, titled Omar Rashid v. X & Ors., is listed for hearing on Wednesday before Justice Sachin Datta. Rashid is seeking damages and legal action over what he has described as a “sinister campaign” against him.

Case Follows Anonymous Social Media Posts

The controversy began in May 2025 after anonymous social media posts accused Rashid, who was then working with The Wire, of serious sexual offences and alleged forced consumption of beef.

The posts also reportedly linked the allegations to communal and political themes involving Kashmir and “love jihad”.

Following the posts, Tanmay N, convenor of the Sahyadri Rights Forum, approached the National Human Rights Commission seeking an investigation. The NHRC registered a case on May 23, 2025, naming Rashid and The Wire, and directed the Delhi Police Commissioner to investigate.

NHRC Closed Case After Police Report

The Delhi Police later submitted an Action Taken Report to the NHRC, stating that no further action was required.

According to Rashid, the police report said the woman whose allegations were circulated online refused to disclose her identity and address and did not want to pursue the matter.

Rashid has also claimed that the police report identified the person behind the posts as a 34 year old practising advocate and political activist. He alleged that the person refused to cooperate with the inquiry and denied making a complaint against him.

The NHRC subsequently closed the proceedings after receiving no response to the police report.

“In view of the above facts and circumstances, the Commission is of the opinion that no further intervention is warranted in the matter. The case is closed,” the NHRC said in its order.

Rashid Alleges Personal and Professional Harm

Rashid has claimed that the social media campaign caused significant personal, professional and financial damage.

He has alleged that the posts were intended to portray him as a “communal monster” and that references to his

Kashmiri Muslim identity, beef and “love jihad” were used to amplify the allegations.

He has also claimed that he received death threats, communal abuse and threats against his family following the posts. According to his account, his personal information was circulated and he received threatening calls and messages, including some from outside India.

Rashid has said he remained silent while the official proceedings were underway because he wanted the authorities to complete their inquiry.

Delhi HC to Hear Defamation Plea

The Delhi High Court had earlier directed the NHRC to conclude its proceedings after Rashid approached the court seeking a time bound decision.

The latest defamation suit seeks legal accountability over the social media allegations. The claims made by Rashid in the suit are now before the Delhi High Court and will be subject to judicial consideration.

The hearing is scheduled before Justice Sachin Datta on September 9.

Source: <https://www.barandbench.com/amp/story/news/delhi-hc-summons-lawyer-who-accused-journalist-omar-rashid-of-sexual-harassment-force-feeding-her-beef>

Delhi HC summons lawyer who accused journalist Omar Rashid of sexual harassment, force feeding her beef

The Court has given the lawyer two weeks to reply to Rashid's plea for interim injunction.

Prashant Jha

Published:9th Sep, 2026 at 11:05 AM

The Delhi High Court on Wednesday issued summons to a lawyer on a defamation suit filed by journalist Omar Rashid.

Rashid has sued the lawyer after she accused him of sexual harassment and force-feeding her beef.

Justice Sachin Datta issued summons to the defendant. The Court also issued notice to her on Rashid's plea for an interim injunction and listed the case for further hearing after two weeks.

Rashid faced allegations in 2025 after an anonymous woman accused him on social media of rape, abuse and forcibly making her consume beef.

The allegations prompted the National Human Rights Commission (NHRC) to register a complaint against him. The Delhi High Court subsequently sought an action-taken report from the Delhi Police on the complaint. After an inquiry lasting more than 300 days, the NHRC closed the matter after Delhi Police found no grounds to proceed with an investigation.

The defamation suit has been filed through Advocate Shaurya Mittal. Advocate Adit S Pujari appeared for Rashid today.

Source: <https://www.aninews.in/news/national/general-news/meta-india-representatives-arrive-at-ncpcr-office-over-cseam-advertisement-allegations20260909164747/>

Meta India representatives arrive at NCPCR office over CSEAM advertisement allegations

ANI | Updated: Sep 09, 2026 16:47 IST

New Delhi [India], September 9 (ANI): Representatives of Meta India arrived at the office of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on Wednesday after the child rights body summoned the company's Managing Director and Head of Meta India in connection with an inquiry into alleged advertisements related to Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM).

The NCPCR had taken suo motu cognisance of a media report published by BBC Eye regarding alleged advertisements on Meta-owned platforms and issued a notice to Meta Platforms, Inc. on July 3, 2026, seeking an explanation over the allegations.

Meta submitted its response to the Commission a week after the notice was issued.

After examining the response, the NCPCR decided to institute an inquiry to ascertain the facts and circumstances surrounding the matter.

As part of the ongoing proceedings, the Commission summoned the MD and Head of Meta India to appear before it on September 9 and provide further information regarding the allegations and the company's response.

The inquiry is aimed at determining the facts surrounding the allegations and examining the response submitted by Meta, the Commission said.

The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier directed the Delhi Police to conduct a comprehensive probe into allegations that paid advertisements on Meta-owned Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India.

The NHRC also directed the police to examine whether the technology company and other concerned entities complied with mandatory reporting obligations under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The NHRC took cognisance of media reports published by the BBC World Service alleging that advertisements on Instagram used particular expressions and redirected users to channels where such material was allegedly being offered for sale.

In a letter dated July 8, the NHRC directed the Commissioner of Police, Delhi, to submit a comprehensive Action Taken Report (ATR) on the matter. The proceedings were initiated after a complaint/intimation dated July 6 was placed before the Commission.

The NHRC subsequently wrote another letter to the Delhi Police on July 29 seeking submission of the requisite report. (ANI)

Source: <https://www.livelaw.in/amp/high-court/delhi-high-court/journalist-omar-rashid-defamation-suit-summons-posts-alleging-rape-force-feeding-beef-549290>

Home > High Courts > Delhi High Court > Delhi High Court Issues...

Delhi High Court Issues Summons In Journalist Omar Rashid's Defamation Suit Over Social Media Posts Alleging Rape, 'Force-Feeding Beef'

By - Nupur Thapliyaltwitter-greylinkedinUpdate: 2026-09-09 05:20 GMT

The Delhi High Court on Wednesday issued summons in the defamation suit filed by journalist Omar Rashid against anonymous women lawyers who posted sexual harassment allegations against him on social media last year.

Justice Sachin Datta issued notice in the interim injunction plea filed by Rashid in view of urgency cited in the same.

The matter is now listed on September 24. Advocate Adit S Pujari appeared for the journalist.

The matter revolves around anonymous social media posts made by two women lawyers accusing Rashid of grave offences, including alleged rape and "force-feeding beef".

Following the said allegations, the National Human Rights Commission (NHRC) had initiated a case against Rashid in May 2025.

After an inquiry lasting over 300 days, the Commission had closed its case against journalist Rashid after the Delhi Police found no grounds to proceed with the investigation. The police investigation concluded there was no action needed in the matter.

One Tanmay N., the convenor of the 'Sahyadri Rights Forum', had approached the NHRC, seeking an investigation against the journalist on the basis of anonymous social media allegations.

Following that, the NHRC had registered a case, which named both Omar Rashid and news portal The Wire (where Omar Rashid was working then), on May 23, 2025 and directed the Delhi Police Commissioner to investigate the allegations.

On October 6, 2025, the Delhi Police Commissioner submitted a report before the NHRC, stating that no further action was required in the matter, as the victim refused to disclose her identity and address, and expressed no interest to pursue the matter.

The NHRC in its proceedings on March 13 stated that no response was received from the complainant with regard to the Delhi Police report.

The NHRC had then concluded that no further intervention was needed in the matter. "In view of the above facts

and circumstances, the Commission is of the opinion that no further intervention is warranted in the matter. The case is closed,” the NHRC had said in its final order.

Title: Omar Rashid v. X & Ors

Source:

<https://www.newsgram.com/amp/story/chhattisgarh/2026/09/09/nhrc-chhattisgarh-school-iron-ladder>

NHRC seeks report over schoolchildren using iron ladder to cross river in Chhattisgarh [IANS]
Chhattisgarh

NHRC Seeks Report Over Schoolchildren Using Iron Ladder to Cross River in Chhattisgarh

Observing that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights, the apex human rights body has issued a notice to the Chhattisgarh Chief Secretary, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

IANS Agency

Published:9th Sep, 2026 at 11:00 PM

Updated:9th Sep, 2026 at 11:00 PM

THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSIONS (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports that dozens of schoolchildren in Chhattisgarh's Gariyaband district are forced to cross a river using a narrow and slippery iron ladder attached to an unfinished bridge to reach their schools.

Observing that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights, the apex human rights body has issued a notice to the Chhattisgarh Chief Secretary, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, children from Khambhatha and nearby settlements in the Mainpur Block area are compelled to climb the iron ladder attached to an incomplete bridge to cross the Pairi river and attend school.

The report said the shallow river turns into a torrent during the monsoon, making the crossing particularly hazardous for the children.

According to the media report, carried on September 3, a roughly 300-metre-long bridge between Deharguda and Khambhatha in Mainpur Block has been under construction for nearly six years. The villagers were reportedly assured by the concerned authorities about a year ago that the bridge would be completed within six months. However, the construction remains incomplete, leaving schoolchildren and residents dependent on the hazardous crossing.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, embodies India's concern for the promotion and protection of human rights. Its primary role is to protect and promote human rights, defined as rights relating to life, liberty, equality and dignity of individuals, guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Source: <https://thenewsmill.com/2026/09/nhrc-seeks-report-from-chhattisgarh-chief-secretary-over-schoolchildren-risking-river-crossing-via-unfinished-bridge/>

NHRC seeks report from Chhattisgarh Chief Secretary over schoolchildren risking river crossing via unfinished bridge

By TNM (With ANI Inputs) 9 September 2026, 8:52 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports that dozens of schoolchildren from Khambhatha and surrounding areas in Gariyaband district, Chhattisgarh, are compelled to climb a narrow, slippery iron ladder attached to an incomplete bridge in order to cross the swollen Pairi River to attend school.

The commission noted that the situation raises serious human rights concerns related to the safety and education of the children. Consequently, it issued an official notice to the Chief Secretary of the Government of Chhattisgarh, requesting a detailed report within two weeks.

According to a media report dated September 3, 2026, the approximately 300-metre-long bridge linking Deharguda and Khambhatha in the Mainpur Block has remained unfinished for nearly six years. The construction delay persists despite firm assurances given by authorities about a year ago that the bridge would be completed within six months.

With the current monsoon season transforming the typically shallow Pairi River into a hazardous torrent, the risk to students forced to use the makeshift ladder daily has significantly increased.

Source: <https://www.deccanchronicle.com/amp/southern-states/telangana/black-magic-allegations-on-harish-nhrc-issues-notice-to-dgp-1986230>

Black Magic Allegations on Harish, NHRC Issues Notice to DGP

Telangana DGP gets four weeks to report on alleged failure to register complaints

By : DC Correspondent

Update: 2026-09-09 18:06 GMT

Hyderabad: Senior BRS leader T. Harish Rao who had been under fire from Congress leaders who had been alleging that he performed black magic rituals, has received some relief with the National Human Rights Commission directing the Telangana Director General of Police to submit an action taken report on the issue.

According to a complaint filed with NHRC, though complaints were submitted at the Osmania University and Vanasthalipuram police stations on August 4, followed by a representation at the DGP's office on August 17, no FIR was registered and no reasons were communicated for the failure to register the case.

According to a press release from Harish Rao's office, the complaint with the NHRC. Noted that persons holding high public offices, including the Chief Minister and a Government Whip, repeatedly made public allegations that Harish Rao had performed tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought.

The NHRC gave four weeks to the DGP to submit his report on the matter.

Source: <https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-demands-report-from-chhattisgarh-chief-secy-over-schoolchildren-forced-to-cross-river-via-unfinished-bridge20260909204958/>

NHRC demands report from Chhattisgarh Chief Secy over schoolchildren forced to cross river via unfinished bridge

ANI | Updated: Sep 09, 2026 20:49 IST

New Delhi [India], September 9 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC), on Wednesday, took suo motu cognisance of reports that dozens of schoolchildren from Khambhatha and neighbouring settlements in Chhattisgarh's Gariyaband district are forced to scale a narrow, slippery iron ladder attached to an incomplete bridge to cross the swollen Pairi River to reach their schools.

Observing that the report raises severe human rights concerns regarding the safety and education of children, the NHRC issued an official notice to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, demanding a detailed report within two weeks.

According to the media report dated September 3, 2026, the roughly 300-meter-long bridge connecting Deharguda and Khambhatha in the Mainpur Block area has remained incomplete for nearly six years.

The prolonged delay comes despite explicit assurances given by authorities to local villagers about a year ago that construction would be finished within six months.

The ongoing monsoon season has turned the shallow Pairi River into a dangerous torrent, severely heightening the risk for students forced to use the makeshift ladder structure daily. (ANI)

Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/nhrc-directs-dgp-to-take-action-over-occult-rituals-claim-against-harish-rao/articleshow/133980576.cms>

NHRC directs DGP to take action over 'occult rituals' claim against Harish Rao
Koride Mahesh Sep 9, 2026, 11.53 PM IST

Hyderabad: The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday has directed the Telangana DGP to take action against those who made unsubstantiated black magic allegations against BRS leader and ex-minister T Harish Rao. The NHRC gave these orders taking cognisance of a complaint regarding the failure to register an FIR over public allegations of "black magic" and "occult rituals" against Harish Rao. The complaint was filed before the NHRC by Telangana high court advocate Karupothula Revanth. The Commission has directed the Telangana DGP, to submit an Action Taken Report (ATR) within four weeks.

According to the complaint, since July 31, 2026, persons holding high public offices, including the chief minister and a govt whip, have repeatedly made public allegations that Harish Rao had performed tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought.

The complaint said that no temple records, priest statements, receipts or other evidence supporting these allegations have so far been made public. It further stated that complaints were submitted at the OU and Vanasthalipuram police stations on Aug 4, followed by a representation at the DGP's office on Aug 17. However, according to the complaint, no FIR was registered and no reasons were communicated for the failure to register the case.

The complaint expressed concern that public statements by persons holding high constitutional and political offices linking rainfall or drought to occult practices could promote superstition among the public. It also warned that such claims could encourage accusations of witchcraft in rural areas and potentially lead to attacks against women, widows, elderly persons and members of SC/ST communities.

Advocate Karupothula Revanth said, "If an ordinary citizen makes such allegations, a case would be registered immediately. But when people in positions of power make such statements, no action is taken. That is the reason this complaint was filed."

Source: <https://newsonair.gov.in/nhrc-seeks-report-over-children-using-iron-ladder-to-cross-river-in-chhattisgarh/>

NHRC seeks report over children using iron ladder to cross river in Chhattisgarh

News On AIR | September 9, 2026 8:57 PM

The National Human Rights Commission has issued a notice to the Chief Secretary of Chhattisgarh over the media report on dozens of children from Khambhatha and nearby settlements in the Mainpur Block in Chhattisgarh, compelled to climb a narrow and slippery iron ladder, attached to an unfinished bridge, to cross the Pairi River to reach their schools. NHRC noted that reportedly, the monsoon turns the shallow river into a torrent. Taking suo motu cognizance, the commission has asked for a detailed report on the matter within two weeks. NHRC highlighted that according to the media report, a roughly 300-metre-long bridge between Deharguda and Khambhatha in Mainpur Block has been under construction for nearly six years despite the villagers having been assured of its completion in six months by the concerned authorities about a year ago.

Source: <https://telanganatoday.com/nhrc-steps-in-on-black-magic-allegations-targeting-harish-rao>

NHRC steps in on black magic allegations targeting Harish Rao

The NHRC has taken cognisance of a complaint regarding the failure to register an FIR over public allegations of “black magic” against Siddipet MLA T Harish Rao.

By Telangana Today

Published Date - 9 September 2026, 10:45 PM

Hyderabad: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint regarding the failure to register an FIR over public allegations of “black magic” and “occult rituals” against Siddipet MLA and BRS Deputy Floor Leader T Harish Rao.

The complaint was filed before the NHRC by Telangana High Court advocate and social activist Karupothula Revanth, with the authorisation of Harish Rao. The Commission has directed the Director General of Police (DGP), Telangana, to submit an Action Taken Report (ATR) in English within four weeks. The direction was issued by the Commission on Wednesday.

Advocate Karupothula Revanth filed the complaint on August 22.

According to the complaint, since July 31, 2026, persons holding high public offices, including the Chief Minister and a Government Whip, have repeatedly made public allegations that Harish Rao had performed tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought. Download Interactive Maps

The complaint states that no temple records, priest statements, receipts or other evidence supporting these allegations have so far been made public.

It further states that complaints were submitted at the Osmania University and Vanasthalipuram Police Stations on August 4, followed by a representation at the DGP's office on August 17. However, according to the complaint, no FIR was registered and no reasons were communicated for the failure to register the case.

The complaint expressed concern that public statements by persons holding high constitutional and political offices linking rainfall or drought to occult practices could promote superstition among the public. It also warned that such claims could encourage accusations of witchcraft in rural areas and potentially lead to attacks against women, widows, elderly persons and members of SC/ST communities.

Source: <https://www.thehindu.com/news/national/tehrangana/nhrc-seeks-dgps-report-on-ignoring-complaint-against-harish-rao/article71448704.ece>

NHRC seeks DGP's report on ignoring complaint against Harish Rao

Published - September 09, 2026 11:51 pm IST - HYDERABAD

The Hindu Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint regarding the failure to register an FIR over public allegations of 'black magic' and 'occult rituals' against Siddipet MLA and former Minister T. Harish Rao. The Commission has directed the Director General of Police (DGP), Telangana, to submit an Action Taken Report (ATR) within four weeks.

According to the complaint by Karupothula Revanth, no temple records, priest statements, receipts or other evidence supporting these allegations have so far been made public but there were repeated public allegations targeting Mr. Harish Rao that he had performed tantric or occult rituals at temples to stop the rains and cause drought.

Complaints were submitted at the Osmania University and Vanasthalipuram Police Stations on August 4, 2026, followed by a representation to the DGP office on August 17, 2026. However, according to the complaint, no FIR was registered, and no reasons were communicated for the failure to register the case.

Published - September 09, 2026 11:51 pm IST

Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/nhrc-seeks-report-on-alleged-exploitation-of-widow-sale-of-newborn/articleshow/133969415.cms>

NHRC seeks report on alleged exploitation of widow, sale of newborn
TNN | Sep 9, 2026, 06.03 PM IST

Ranchi: National Human Rights Commission (NHRC) has directed Ranchi SSP to investigate allegations concerning the exploitation of a 35-year-old widow and the sale of her newborn child. It has sought an action taken report within four weeks.

The commission took cognisance of a complaint filed by Baidnath Kumar, secretary of the Child Rights Foundation, Ranchi.

According to the complaint, a man identified as Dinesh Dole allegedly lured the woman with the promise of employment before trafficking and confining her. He allegedly sexually exploited her and forced her into prostitution.

The woman gave birth to a boy in Ranchi on Nov 11, 2025. The complainant alleged that the newborn was subsequently taken away and sold to another person without the mother's consent.

A criminal case was registered at Hindpiri police station in Ranchi on May 14. However, the child is yet to be reunited with the woman, while the main accused remains at large, the complaint said.

Kumar sought the commission's intervention for the child's immediate recovery and stringent action against Dole and his alleged accomplices.

NHRC had initially directed the SSP to investigate the allegations and submit an action taken report within two weeks. As the report has not been received, the commission has given the police another four weeks to comply. The commission warned that it could initiate coercive action if its direction is not complied with by Oct 16.

Source: <https://hindi.livelaw.in/amp/delhi-high-court/omar-rashid-delhi-high-court-defamation-sexual-harassment-me-too-justice-sachin-datta-549318>

Home > हाईकोर्ट > दिल्ली हाईकोर्ट > दुष्कर्म और 'बीफ खिलाने'...

दुष्कर्म और 'बीफ खिलाने' का आरोप: पत्रकार उमर

By - Amir Ahmad Update: 2026-09-09 06:57 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार उमर राशिद की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली दो अज्ञात महिला वकीलों के खिलाफ समन जारी किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उमर राशिद पर दुष्कर्म और कथित तौर पर जबरन बीफ खिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।

जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले में अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। याचिका में मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अदालत से तत्काल राहत की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। पत्रकार उमर राशिद की ओर से वकील अदित एस. पुजारी अदालत में पेश हुए।

मामला पिछले साल सोशल मीडिया पर सामने आई दो अज्ञात महिला वकीलों की पोस्ट से जुड़ा है। इन पोस्ट में उमर राशिद पर यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए। आरोपों में दुष्कर्म और कथित तौर पर जबरन बीफ खिलाने का आरोप भी शामिल है।

इन सोशल मीडिया आरोपों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मई 2025 में उमर राशिद के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता के तौर पर 'सह्याद्रि राइट्स फोरम' के संयोजक तन्मय एन. ने आयोग का रुख किया। उन्होंने अज्ञात सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पत्रकार के खिलाफ जांच की मांग की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 23 मई 2025 को मामले का संज्ञान लेते हुए उमर राशिद और उस समय उनके कार्यरत समाचार पोर्टल 'द वायर' का नाम भी कार्यवाही में शामिल किया। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को आरोपों की जांच के निर्देश दिए।

करीब 300 दिन से अधिक चली कार्यवाही के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में आगे जांच की जरूरत नहीं बताई। 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि कथित पीड़िता ने अपनी पहचान और पता बताने से इनकार किया और वह मामले को आगे बढ़ाने में भी इच्छुक नहीं थी।

आयोग की 13 मार्च की कार्यवाही में यह भी दर्ज किया गया कि पुलिस की रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद आयोग ने मामले में आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानी और कार्यवाही बंद की।

आयोग ने अपने अंतिम आदेश में कहा था,

“उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग की राय है कि मामले में आगे किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मामला बंद किया जाता है।”

अब उमर राशिद ने सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में समन जारी करते हुए अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है।

मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/meerut/legal-awareness-is-essential-to-protect-human-rights-anjani-anuj-meerut-news-c-72-1-mct1014-159085-2026-09-09>

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी जागरूकता जरूरी : अंजनी अनुज

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो

Updated Wed, 09 Sep 2026 05:39 PM IST

सीसीएसयू में एक दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

संवाद न्यूज एजेंसी

मेरठ। मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज में संवैधानिक मूल्यों, कानूनी अधिकारों और मानवीय गरिमा के प्रति जागरूकता जरूरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं इन अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

यह बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के प्रेजेंटिंग ऑफिसर अंजनी अनुज ने वह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के सेमिनार हॉल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंजनी अनुज, विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर प्रो. बीरपाल सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के कोऑर्डिनेटर डॉ. विवेक कुमार और कार्यक्रम संयोजक आशीष कौशिक मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि अंजनी अनुज ने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों तथा सामूहिक अधिकारों की जानकारी दी। प्रो. बीरपाल सिंह ने मानवाधिकार और शोध के संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों का शोध समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान में उपयोगी होना चाहिए। संसद टीवी के श्री रामवीर श्रेष्ठ ने मानवाधिकारों के संवैधानिक आधार की जानकारी दी। डॉ. विवेक कुमार ने कहा कि मानवाधिकार शिक्षा को केवल पुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। डॉ. अपेक्षा चौधरी, डॉ. सुदेशना और डॉ. विकास कुमार ने विभिन्न सत्रों में प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। कार्यक्रम में डॉ. कुसुमा वती, डॉ. धनपाल, डॉ. महिपाल सिंह, डॉ. सुशील कुमार शर्मा, डॉ. मीनाक्षी समेत शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

Source: <https://bharatexpress.com/legal/satya-niketan-building-collapse-delhi-hc-pil-du-hostels-687837>

सत्य निकेतन हादसे में 7 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन? दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा- 'छात्रों के लिए हॉस्टल क्यों नहीं?'

Delhi High Court News: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

गोपाल कृष्ण

September 9, 2026 2:52 pm

Edited by Shubhra Rai

Delhi High Court News: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दायर जनहित याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

कोर्ट ने एनएचआरसी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा

दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर प्रोग्राम में करीब 1.32 लाख छात्र एनरोल्ड हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में छात्रों के लिए होस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है. दायर याचिका में कहा गया है कि होस्टल की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को निजी मकानों और किराए की इमारतों में रहना पड़ता है. ऐसे में पुरानी और असुरक्षित इमारतों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं. बता दें कि सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी. जिनमें 5 छात्र थे.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भवन के मालिक हरिराम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला और उनके बेटे महेश के खिलाफ दक्षिण परिसर थाने में मामला दर्ज किया. तीनों पर गैर इरादतन हत्या, इमारत में रखरखाव में लापरवाही और लोगों की सुरक्षा खतरे में डालने समेत कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई. इससे पहले सत्य निकेतन घटना की जांच की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने एनएचआरसी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

कोर्ट ने होस्टल व्यवस्था को लेकर कई सवाल किए

मामले की सुनवाई के दौरान हादसे को बेहद दुखद बताया है. कोर्ट ने कहा था इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा था, पीड़ितों के माता-पिता की भावनाओं को समझा जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता है. कोर्ट ने पीड़ितों के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कहा था वीडियो शेयर करना सही नहीं है. साथ ही कोर्ट ने भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा था. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने होस्टल व्यवस्था को लेकर कई सवाल किए.

कोर्ट ने एमसीडी से पूछा कि क्या होस्टल के लिए कोई नियम है. कोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछा था कि कॉलेजों में बाहर के कितने छात्र पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में कितने होस्टल है, उसमें कितने बच्चे रह सकते हैं. कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और सरकार से रिपोर्ट तलब किया था. कोर्ट ने पीजी और होस्टल की जांच के लिए अहम निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि फ्लैटों में भी छात्र रह रहे हैं, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी. किराए के फ्लैट में पीजी चल रहा है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए.

Source: <https://hindi.theprint.in/india/youth-dies-due-to-snake-bite-human-rights-commission-issues-notice-to-all-states-union-territories/1025917/>

सांप के काटने से युवक की मौत : सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मानवाधिकार आयोग का नोटिस
भाषा 9 September, 2026

नई दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सांप के काटने के बाद इलाज नहीं हो पाने के कारण एक युवक की मौत के मामले में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को नोटिस जारी किया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आयोग ने यह कदम एक शिकायत के आधार पर उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चित्रकूट के जिला अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही और आपात जीवन रक्षक सुविधाओं की कमी के कारण युवक की मौत हुई।

मामले की एक सितंबर की कार्यवाही के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सांप के काटने के तुरंत बाद पीड़ित को जिला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन उसे समय पर आपात चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। उसे एंटी स्नेक वेनम (एसवी), वेंटिलेटर या आईसीयू जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं और पर्याप्त आपात परिवहन व्यवस्था के बिना प्रयागराज रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि जिला अस्पताल में जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्री की अनुपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के खंडेहा गांव में जहरीले सांप के काटने के बाद युवक की मौत गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही, इलाज में देरी और जिला अस्पताल में आपात जीवन रक्षक सुविधाओं के पूरी तरह अभाव के कारण हुई।

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, सभी जिला अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

मानवाधिकार आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े प्रतीत होते हैं।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है।

आयोग ने राज्य प्राधिकारियों को उच्च जोखिम वाले ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने, सांप काटने की घटनाओं का आंकड़ा जुटाने और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कानूनगो ने बाद में 'पीटीआई वीडियो' से बातचीत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए नोटिस के बारे में जानकारी दी।

भाषा मनीषा वैभव

Source: <https://www.livehindustan.com/national/story-human-rights-commission-investigates-suspected-half-encounter-of-property-dealer-in-mushahari-201788964568205.amp.html>

हाफ एनकाउंटर का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा

Sep 10, 2026 01:05 am IST

By Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर

भटौलिया नहर के पास प्रॉपर्टी डीलर अंकित रंजन हत्याकांड में अमित सिंह के हाफ एनकाउंटर का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा। सामाजिक कार्यकर्ता देवव्रत कुमार सहनी ने सीबीआई या सीआईडी जांच की मांग की, आरोपित के फरार होने और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

मुशहरी, हिसं। भटौलिया नहर के पास प्रॉपर्टी डीलर अंकित रंजन हत्याकांड के आरोपित अमित सिंह के हाफ एनकाउंटर का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया। सामाजिक कार्यकर्ता देवव्रत कुमार सहनी ने आयोग में याचिका दायर कर घटना को संदिग्ध बताते हुए सीबीआई या सीआईडी से जांच कराने की मांग की है। याचिका में पुलिस की घेराबंदी के बावजूद दूसरे आरोपित के फरार होने, घायल अमित सिंह को परिजनों से नहीं मिलने देने और मुठभेड़ की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग और पुलिसकर्मियों के कॉल डिटेल की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। 17 जून की देर रात पुलिस भटौलिया बांध पर वाहन जांच कर रही थी।

इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों के भागने पर पुलिस ने पीछा किया। पुलिस के अनुसार, बदमाशों की गोलीबारी के जवाब में की गई कार्रवाई में अमित सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद होने की बात कही गई थी।

Source: <https://samacharnama.com/news/hindi-nhrc-seeks-report-over-schoolchildren-using-iron/cid19231779.htm>

छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को नदी पार करने के लिए लोहे की सीढ़ी का सहारा, एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान
By Samacharnama Desk Sep 9, 2026, 23:44 IST

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है, जिनके अनुसार छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दर्जनों स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए एक अधूरे पुल से जुड़ी संकरी और फिसलन भरी लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल करके नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी अगर सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसे देखते हुए, देश की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मैनपुर ब्लॉक इलाके के खंभाथा और आस-पास की बस्तियों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए पैरी नदी पार करने के लिए एक अधूरे पुल पर लगी लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कम गहरी यह नदी मानसून के दौरान उफान पर आ जाती है, जिससे बच्चों के लिए इसे पार करना बहुत खतरनाक हो जाता है।

3 सितंबर को आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मैनपुर ब्लॉक में देहारगुडा और खंभाथा के बीच लगभग 300 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पिछले छह साल से चल रहा है। बताया जाता है कि संबंधित अधिकारियों ने लगभग एक साल पहले ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि पुल का काम छह महीने में पूरा हो जाएगा। हालांकि, निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है, जिससे स्कूली बच्चे और स्थानीय निवासी खतरनाक रास्ते से नदी पार करने को मजबूर हैं।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है, जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका मुख्य काम मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना है। मानवाधिकारों का अर्थ है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े अधिकार, जिनकी गारंटी संविधान देता है या जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों में शामिल हैं और जिन्हें भारत की अदालतों में लागू कराया जा सकता है।

देश की इस शीर्ष मानवाधिकार संस्था के पास यह अधिकार है कि वह मानवाधिकार उल्लंघन की औपचारिक शिकायत मिले बिना भी मीडिया रिपोर्ट, सार्वजनिक जानकारी या अन्य स्रोतों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर सकती है।

--आईएनएस

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-nhrc-seeks-report-over-schoolchildren-using-iron-ladder-to-cross-river-in-chhattisgarh-20260909173821-1358192>

Home /अन्य /छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को नदी...

छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को नदी पार करने के लिए लोहे की सीढ़ी का सहारा, एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान
9 Sept 2026 11:56 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है, जिनके अनुसार छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दर्जनों स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए एक अधूरे पुल से जुड़ी संकरी और फिसलन भरी लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल करके नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

ई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है, जिनके अनुसार छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दर्जनों स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए एक अधूरे पुल से जुड़ी संकरी और फिसलन भरी लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल करके नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नए स्थान तलाशें

मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी अगर सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसे देखते हुए, देश की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मैनपुर ब्लॉक इलाके के खंभाथा और आस-पास की बस्तियों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए पैरी नदी पार करने के लिए एक अधूरे पुल पर लगी लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम गहरी यह नदी मानसून के दौरान उफान पर आ जाती है, जिससे बच्चों के लिए इसे पार करना बहुत खतरनाक हो जाता है। 3 सितंबर को आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मैनपुर ब्लॉक में देहारगुडा और खंभाथा के बीच लगभग 300 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पिछले छह साल से चल रहा है। बताया जाता है कि संबंधित अधिकारियों ने लगभग एक साल पहले ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि पुल का काम छह महीने में पूरा हो जाएगा। हालांकि, निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है, जिससे स्कूली बच्चे और स्थानीय निवासी खतरनाक रास्ते से नदी पार करने को मजबूर हैं।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है, जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका मुख्य काम मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना है। मानवाधिकारों का अर्थ है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े अधिकार, जिनकी गारंटी संविधान देता है या जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों में शामिल हैं और जिन्हें भारत की अदालतों में लागू कराया जा सकता है। देश की इस शीर्ष मानवाधिकार संस्था के पास यह अधिकार है कि वह मानवाधिकार उल्लंघन की औपचारिक शिकायत मिले बिना भी मीडिया रिपोर्ट, सार्वजनिक जानकारी या अन्य स्रोतों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर सकती है।

Source: <https://cgkhabar.com/news/gariaband-school-children-forced-to-cross-river-using-an-iron-ladder-nhrc-issues-notice-20260909>

गरियाबंद: लोहे की सीढ़ी के सहारे नदी पार करने को मजबूर स्कूली बच्चे, NHRC ने भेजा नोटिस
9 सितंबर 2026 CG Khabar

नई दिल्ली । डेस्क: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चों के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाया है। मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कृषि और वानिकी

मिली जानकारी के अनुसार, गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक स्थित खंभाथा और आसपास के ग्रामीण इलाकों के दर्जनों बच्चे पढ़ाई के लिए पैरी नदी पार करने को मजबूर हैं। नदी पर बन रहा पुल अधूरा पड़ा है, जिससे बच्चे पुल से लगी एक संकरी और फिसलन भरी लोहे की सीढ़ी के सहारे नदी पार करते हैं।

मानसून के दौरान नदी का जलस्तर और बहाव काफी तेज हो जाता है, जिससे यह सफर बच्चों की जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।

NHRC ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक बेहद गंभीर मामला है। आयोग ने प्रशासन की इस अनदेखी पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। भौगोलिक संदर्भ

बताया जा रहा है कि मैनपुर ब्लॉक के देहरगुड़ा और खंभाथा के बीच बन रहे इस 300 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पिछले छह सालों से अटका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि एक साल पहले संबंधित अधिकारियों ने छह महीने के भीतर काम पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है।

पुल का निर्माण पूरा न होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को रोजाना इस जानलेवा रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

Source: <https://www.prabhasakshi.com/national/nhrc-notice-states-over-chitrakoot-snakebite-death>

NHRC ने चित्रकूट में Snakebite से युवक की मौत पर सभी राज्यों को भेजा नोटिस
प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 9 2026 12:23PM

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला अस्पताल में समय पर इलाज और जीवन रक्षक सुविधाएं न मिलने से युवक की जान जाने पर मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। नई दिल्ली, नौ सितंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सांप के काटने के बाद इलाज नहीं हो पाने के कारण एक युवक की मौत के मामले में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आयोग ने यह कदम एक शिकायत के आधार पर उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चित्रकूट के जिला अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही और आपात जीवन रक्षक सुविधाओं की कमी के कारण युवक की मौत हुई।

मामले की एक सितंबर की कार्यवाही के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सांप के काटने के तुरंत बाद पीड़ित को जिला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन उसे समय पर आपात चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। उसे एंटी स्नेक वेनम (एसवी), वेंटिलेटर या आईसीयू जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं और पर्याप्त आपात परिवहन व्यवस्था के बिना प्रयागराज रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि जिला अस्पताल में जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्री की अनुपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के खंडेहा गांव में जहरीले सांप के काटने के बाद युवक की मौत गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही, इलाज में देरी और जिला अस्पताल में आपात जीवन रक्षक सुविधाओं के पूरी तरह अभाव के कारण हुई। शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, सभी जिला अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का निर्देश देने का अनुरोध किया। मानवाधिकार आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े प्रतीत होते हैं। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य प्राधिकारियों को उच्च जोखिम वाले ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने, सांप काटने की घटनाओं का आंकड़ा जुटाने और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कानूनगो ने बाद में 'पीटीआई वीडियो' से बातचीत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए नोटिस के बारे में जानकारी दी।

Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/legal/legal-news-umar-rashid-defamation-case-delhi-high-court-social-media-allegations-nhrc-probe-closed/amp_articleshow/133956297.cms

hindi NewsLegal News Umar Rashid Defamation Case Delhi High Court Social Media Allegations Nhrc Probe Closed

Legal news: NHRC ने बंद की जांच, अब सोशल मीडिया के आरोपों पर पत्रकार उमर राशिद पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

सोशल मीडिया पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पत्रकार उमर राशिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। NHRC ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद जांच बंद कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

Authored by: प्राची यादव

Contributed by: टीना

Updated: 9 Sept 2026, 12:08 pm IST | नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर लगाए गए बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा बंद किए जाने के बाद पत्रकार उमर राशिद ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राशिद ने अज्ञात महिला वकीलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हाई कोर्ट ने मामले में समन जारी करते हुए अंतरिम राहत की उनकी मांग पर बुधवार नोटिस जारी किया।

जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिका पर नोटिस जारी किया।

पत्रकार की ओर से वकील आदित एस. पुजारी पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

विवाद पिछले साल सोशल मीडिया पर की गई कुछ अज्ञात पोस्ट से जुड़ा है।

इन पोस्ट में राशिद पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए गए थे।

एक पोस्ट में उन पर कथित तौर पर किसी को “जबरदस्ती बीफ खिलाने” का भी गंभीर आरोप लगाया गया था।

राशिद ने इन आरोपों को झूठा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए अदालत से राहत मांगी है।

NHRC ने भी शुरू की थी जांच, दिल्ली पुलिस को सौंपी गई थी जिम्मेदारी

इस मामले में पहले NHRC ने भी जांच शुरू की थी। सह्याद्री राइट्स फोरम के संयोजक तन्मय एन. की शिकायत पर आयोग ने 23 मई 2025 को मामले का संज्ञान लिया था। शिकायत में सोशल मीडिया पर किए गए अज्ञात दावों का जिक्र था। इसमें राशिद के साथ उस न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ का नाम भी शामिल था, जहां वह उस समय काम कर रहे थे। NHRC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आरोपों की औपचारिक जांच करने के निर्देश दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 6 अक्टूबर 2025 को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे कार्रवाई का कोई आधार नहीं मिला।

जांच बंद होने के बाद राशिद ने अदालत का रुख किया

जांच में सामने आया कि कथित पीड़िता ने अपनी पहचान या पता बताने से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक, उसने मामले को आगे बढ़ाने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। बाद में NHRC ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने भी पुलिस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इन परिस्थितियों में आयोग ने जांच बंद कर दी और कहा कि मामले में आगे किसी दखल की जरूरत नहीं है। अब NHRC की कार्यवाही खत्म होने के बाद राशिद ने सोशल मीडिया पर लगाए गए अज्ञात आरोपों के खिलाफ मानहानि मामले में अदालत से कानूनी राहत मांगी है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/india/chitrakoot-snakebite-death-nhrc-issues-notice-to-all-states-uts-over-lack-of-life-saving-drugs/articleshow/133979365.cms>

चित्रकूट सांप डंसने का मामले में अस्पताल में एंटी-वेनम और वेंटिलेटर न मिलने पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

Edited by: दीपांशु | भाषा • 9 Sept 2026, 11:42 pm IST

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सांप के काटने के बाद सही इलाज और आपातकालीन सुविधाएं न मिलने से हुई युवक की मौत पर एनएचआरसी (NHRC) ने बड़ा एक्शन लिया है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सांप के काटने के बाद इलाज नहीं हो पाने के कारण एक युवक की मौत के मामले में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को नोटिस जारी किया है।

सुविधाओं की कमी के कारण युवक की हुई मौत

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने यह कदम एक शिकायत के आधार पर उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चित्रकूट के जिला अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही और आपात जीवन रक्षक सुविधाओं की कमी के कारण युवक की मौत हुई।

शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप

मामले की एक सितंबर की कार्यवाही के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सांप के काटने के तुरंत बाद पीड़ित को जिला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन उसे समय पर आपात चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। उसे एंटी स्नेक वेनम (एसवी), वेंटिलेटर या आईसीयू जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं और पर्याप्त आपात परिवहन व्यवस्था के बिना प्रयागराज रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई।

क्या था पूरा मामला

अधिकारियों के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि जिला अस्पताल में जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्री की अनुपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के खंडेहा गांव में जहरीले सांप के काटने के बाद युवक की मौत गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही, इलाज में देरी और जिला अस्पताल में आपात जीवन रक्षक सुविधाओं के पूरी तरह अभाव के कारण हुई।

शिकायतकर्ता ने किया अनुरोध

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, सभी जिला अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

दो हफ्ते के अंदर जमा करें रिपोर्ट

मानवाधिकार आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े प्रतीत होते हैं। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है।

नोटिस के बारे में दी जानकारी

आयोग ने राज्य प्राधिकारियों को उच्च जोखिम वाले ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने, सांप काटने की घटनाओं का आंकड़ा जुटाने और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कानूनगो ने बाद में 'पीटीआई वीडियो' से बातचीत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए नोटिस के बारे में जानकारी दी।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/meerut/news/ccsu-meerut-nhrc-human-rights-training-program-students-update-138980037.html>

Hindi NewsLocalUttar pradeshMeerutNHRC Human Rights Training Program At CCSU Meerut | Student Awareness

मानवाधिकार संरक्षण के लिए छात्रों को दी ट्रेनिंग: NHRC ने विद्यार्थियों को बताए मानवाधिकार संरक्षण के तरीके, 200 ने लिया प्रशिक्षण
श्रेया शर्मा | मेरठ 15 घंटे पहले

मानवाधिकारों के संरक्षण और विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को विश्वविद्यालय में एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आर्थिक सहयोग से हुआ। इसमें आयोग की ओर से अंजनी अनुच ने विद्यार्थियों को मानवाधिकार संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला के निर्देशन में कार्यक्रम के आयोजन का प्रस्ताव NHRC को भेजा गया था। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद आयोग के सहयोग से ट्रेनिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम को करीब चार सत्रों में बांटा गया।

उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, कार्यप्रणाली और आम लोगों की आयोग तक पहुंच के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग में शिकायत या प्रार्थना पत्र किस तरह भेजा जा सकता है।

इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली और वहां शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। विशेष सत्रों में अनुसूचित जाति से जुड़े वर्गों के मानवाधिकारों के संरक्षण और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों की जानकारी दी गई।

किसी मामले में मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति सामने आने पर उसे आयोग के संज्ञान में लाने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

200 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

कार्यक्रम में मेरठ के विभिन्न लॉ कॉलेजों और अन्य संस्थानों के अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत कई स्थानों से आए करीब 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

अधिकारियों और विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से मानवाधिकारों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।